THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) Yes, Sir. The cumulative losses of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited are provisionally estimated at Rs. 546 crores as on 31-3-1992. The production level of key products varies from 20% to 104%. However, production had to be curtailed on account of constraints of working capital.

(b) and (c) A Voluntary Retirement Scheme, based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (BPE) in October, 1988, has been introduced in IDPL in 1991. The company has excess manpower and it is one of the causes of the sickness of the company. So far 774 employees including officers, supervisors and workers have taken voluntary retirement in accordance with the said scheme.

(d) and (e) The major reasons of losses of IDPL are high wage component, low capacity utilisation, obsolescence in technology, high interest burden and fixed costs, constraints of working capital and marketing constraints. A proposal for revival of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited has been prepared. The proposal also envisages restructuring of the capital, expansion of capacities of Penicillin G, Vitamins, setting up of captive power facilities and sub-stations at Rishikesh and Hyderabad besides funding of renewals/replacements, working capital requirements, repayment of loans, discontinuation of non-remunerative activities. The proposal also involves write-off of Government loans and interest. The proposal has been under consideration of the Government and its viability is still to be established. Meanwhile, the company has, in compliance of the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, referred its case to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).

उर्वरकों का आयात

508. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्वरकों का उत्पादन उनकी मांग के अनुरूप नहीं हो रहा है और इसके कारण देश को प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर उर्वरकों का आयात करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक उर्वरक की कितनी-कितनी मात्रा का आयात करने का विचार रखती है और उस पर होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त उर्वरकों के कब तक भारत में पहुंच जाने की संभावना है और इसका भुगतान किन-किन विदेशी मुद्राओं में किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंता मोहन) : (क) नाइट्रोजनी उर्वरकों के सम्बन्ध में मांग को अधिकांशतः स्वदेशी उत्पादन के जरिए पूरा किया जाता है । फास्फेटिक उर्वरकों के सम्बन्ध में हमारी आवश्यकता का वृहद मांग स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाता है पोटाशिक उर्वरकों के लिए हम पूर्णतः आयात पर निर्भर है ।

(ख) सरणीबद्ध उर्वरकों का आयात समय-समय पर की गयी समीक्षा के आधार पर किया जाता है । चालू वर्ष के दौरान आयात किये जाने वाले प्रत्येक उर्वरक की ठीक-ठीक मात्रा को बतला पाना सम्भव नहीं है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्तूबर 1992 तक खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम. एम. टी. सी.) जो एक सरणीबद्ध अभिकरण है, ने उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा के लिए ठेका लिया है :—

सामग्री	मात्रा लाख टनों में	लागत एवं भाड़ा (मिलियन अमेरिकी डालर लगभग)
डी॰ए॰पी॰	15.95	305.97
एम॰ओ॰पी॰	18.65	264.82
एस॰ओ॰पी॰	0.05	1.09
एन॰पी॰के॰	1.30	27.48
यूरिया	17.19	260.43

डी ए पी का आयात सितम्बर 1992 से गैर सरणीबद्ध किया गया है और इसलिए सरकार द्वारा डी ए पी की किसी अन्य मात्रा के लिए ऐसे ठेके का प्रश्न ही नहीं उठता । पोटाश के सम्बन्ध में, ऐसा लगता है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही आयात की गयी मात्रा और पहले से किए गए ठेकों के तहत आयात की जाने वाली मात्रा हमारी जरूरत से अधिक होगी । जहां तक यूरिया का सम्बन्ध है कुछ और मात्रा में आयात के लिए ठेका करना होगा ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर 1992 तक ठेका की गयी मात्रा में से तथा गत वर्ष के बाकी ठेकों में से 31 अक्टूबर 1992 तक देश में 15.34 लाख टन डी ए पी, 14.81 लाख टन एम ओ पी, 12.44 लाख टन यूरिया तथा 1.30 लाख टन एन पी के उर्वरक पहुंच चुके हैं । नवम्बर 1992 के दौरान लगभग 1.27 लाख टन एम ओ पी, 2.65 लाख टन यूरिया तथा 5000 टन एस ओ पी के पहुंचने की आशा है । बाकी महीनों के दौरान आगमन अगले ठेकों और वेसेल्स की नियत तिथि पर निर्भर करेगा । सामान्यतः आयातित उर्वरकों के लिए भुगतान अमेरिकी डालर में किया जाता है । चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया से किये के आयातों का भुगतान अब भी रुपये में किया जाता है ।

Reduction in Custom Duty on Bulk Drugs

509. SHRIMATI SATYA BAHIN :

SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the reasons for reduction in Custom Duty on bulk drugs;

(b) whether the objective of custom duty reduction have been achieved; and if so, what are the details thereof;

(c) whether it is a fact that except in case of Cefotaxin, no benefit has been passed on to the public;

(d) what are the names of bulk drugs and formulations on which benefit has been passed on to the consumer;

(e) whether in the case of Cefotoxin formulations also, formulators enjoyed unintended benefits which have not been recovered;

(f) if so, the reasons therefor; and

(g) when the Custom Duty was reduced in each case and its price reduced and what is the amount of unintended benefit made by each ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) Reduction in Customs Duty is done to ensure availability of the bulk drug and avoid shortages of formulations based on it.

(b) Yes, Sir. There have been no serious shortages and the availability has been maintained.

(c) to (g) The benefit of customs duty reductions passed on to the consumers cannot be quantified since the price of formulations depends on a number of